



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336।

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2009/ज्येष्ठ 20, 1931

No. 336।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2009/JYAISTHA 20, 1931

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2009

सा.का.नि. 394(अ)।—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी वित्तीय नियम, 2009 नामक निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, बनाने का प्रस्ताव करती है, धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतीलिस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

ऐसे सभी आक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी वित्तीय नियम, 2009 है;
(2) यह राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) अभिप्रेत है;

(ख) “केन्द्रीय सरकार” से केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ग) “केन्द्रीय निधि” से धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली लागत अभिप्रेत है;

(घ) “राष्ट्रीय निधि” से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि अभिप्रेत है;

(ङ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) “राज्य निधि” से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य रोजगार गारंटी निधि अभिप्रेत है;

(छ) “राज्य सरकार” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी हैं;

(ज) “राज्य के अंश” से धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा पूरी की जानी वाली लागत अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु इसमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. राष्ट्रीय निधि -

(1) राष्ट्रीय निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक लेखे में रखी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय निधि का उपयोग अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट खर्च में केन्द्रीय सरकार के अंश राज्य सरकारों के अनुदानों, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के व्ययों और ऐसे अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुरूपित हों।

4. राज्य निधि - (1) राज्य सरकार किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में धारित की जाने वाली एक राज्य निधि स्थापित कर सकेगी, जो कभी समाप्त न होने वाली होगी।

(2) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपने देय अंश को, केन्द्रीय निधि से धन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर राज्य निधि में जमा करेगी।

5. कतिपय दशाओं में राज्य सरकारों को उधार देना -

(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार राज्य या जिले को इन नियमों में विनिर्दिष्ट औपचारिकताएं पूरा होने के लंबित रहने के दौरान आपात आवश्यकताओं और निधियों की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए उतने उधार दे सकेगी, जितने वह आवश्यक समझे।

(2) केन्द्रीय सरकार, निधियों के अनुचित उपयोग, अधिनियम और/या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्युक्त अनुपालन के लिए राज्य या जिले को केन्द्रीय निधियों का दिया जाना

निलंबित कर सकेगी ; परंतु ऐसा दिया जाना संबंधित राज्य या जिले द्वारा उपचारात्मक उपायों के पुनर्स्थापन के पश्चात् ही प्रभावी किया जाएगा ।

परंतु यह और इस उपधारा के अधीन केन्द्रीय निधियों के दिए जाने को निलंबित किया जाना राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 7 के अधीन बेरोजगार भत्ते का संदाय करने के उसके दायित्व से विमुक्त नहीं करेगा ।

(3) राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से राज्य निधि द्वारा प्राप्त या जिले या किसी अन्य अभिकरण द्वारा सीधे प्राप्त अनुदानों के संबंध में कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा ।

6. केन्द्रीय निधि की मात्रा - राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली केन्द्रीय निधि की मात्रा निम्नानुसार श्रमिक मांग और परियोजनाओं की शेल्फ के निर्धारण के पश्चात् अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (6) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए श्रमिक बजट के आधार पर अवधारित की जाएगी :-

(क) ग्राम पंचायत आगामी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली संभावित श्रमिक मांग का अनुमान लगाएगी और उन परियोजनाओं की पहचान करेगी जो ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार अनुमानित श्रमिक मांग को पूरा करने के लिए प्रत्याशित हों ।

(ख) ग्राम पंचायत प्रत्येक संकर्म के लिए पूर्विकता निर्धारित करेगी और निष्पादन अभिकरणों के नाम की सिफारिश करेगी ।

(ग) ग्राम पंचायत अपने संकल्प की एक प्रति और प्रत्येक वर्ष सितम्बर के अंत तक ग्राम सभा और वार्ड सभाओं के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की प्रति के साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी ।

(घ) कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत ब्लाक योजना और परियोजनाओं के सेल्फ में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की संवीक्षा और समन्वयन पूरा करेगा और ग्राम पंचायतों से प्रस्तावों की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उसका मध्यवर्ती पंचायत के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा ।

(ङ) मध्यवर्ती पंचायत ग्राम पंचायत द्वारा यथा उपदर्शित विभिन्न संकर्मों के बीच पूर्विकता बनाएगा और केवल ऐसे संकर्मों को सम्मिलित करेगा जिनमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें अंतर्वलित हों ।

(च) मध्यवर्ती पंचायत कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ब्लाक योजना प्रस्तुत किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर उसे अंतिम रूप देगा और अनुमोदित करेगा ।

(छ) यदि मध्यवर्ती पंचायत अनुबंधित समय के भीतर ब्लाक योजना का अनुमोदन नहीं करती है तो उसे मध्यवर्ती पंचायत द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा ।

(ज) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के अंत तक जिला कार्यक्रम समन्वयक को ब्लाक योजना प्रस्तुत करेगा ।

(झ) जिला कार्यक्रम समन्वयक जिले में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए पूर्वानुमानित मांग के अनुसार ब्लाक योजनाओं की संवीक्षा करेगा और संकर्म की उपयुक्तता और पर्याप्तता के साथ ही उनकी तकनीकी और वित्तीय साध्यता की परीक्षा करेगा ।

(ज) जिला कार्यक्रम समन्वयक ब्लाक योजना में उपदर्शित किए गए अनुसार ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती ग्राम पंचायत संकर्मों की पूर्विकता बनाए रखेगा ।

(ट) संकर्मों की अपर्याप्तता की दशा में जिला कार्यक्रम समन्वयन उन संकर्मों को सम्मिलित कर सकेगा जिनकी अधिकारिता एक से अधिक ब्लाकों तक फैली है ।

(ठ) जिला कार्यक्रम समन्वयन ब्लाक योजनाओं को समेकित जिला योजना में सम्मिलित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि खर्च के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत संकर्म ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाएं :

परंतु जहां ऐसे संकर्म हैं जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित नहीं किया जाना है वहां जिला योजना में सम्मिलित संकर्म के लिए निष्पादन अभिकरणों को उपदर्शित किया जाएगा ।

(ड) जिला योजना में अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1 में निर्दिष्ट संकर्मों की पूर्विकता अंतर्विष्ट होगी और अधिनियम में अनुबंधित संकर्मों की पूर्विकता से विचलन की दशा में जिला विकास कार्यक्रम समन्वयक जिला योजना के साथ एक स्पष्टीकारक टिप्पण संलग्न करेगा ।

(ढ) जिला कार्यक्रम समन्वयक समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में जिला योजना पर आधारित श्रमिक बजट तैयार करेगा ।

(ण) यदि रोजगार में तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है तो उसके लिए श्रमिक बजट में स्पष्ट रूप से समुचित औचित्य दिया जाएगा ।

(त) जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक वर्ष नवम्बर के अपश्चात् जिला पंचायत को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जिला योजना, ब्लाकवार परियोजनाओं की सेल्फ और श्रमिक बजट प्रस्तुत करेगा ।

(थ) जिला पंचायत परियोजनाओं की तकनीकी मंजूरी और प्रशासनिक मंजूरी सहित जिला योजना, ब्लाकवार परियोजना सेल्फ और श्रमिक बजट को अंतिम रूप देगा तथा अनुमोदित करेगा ।

(द) जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के अपश्चात् राज्य सरकार को यह प्रभावित करते हुए श्रमिक बजट अग्रेषित करेगा कि श्रमिक बजट जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

(ध) समस्त कार्यवाही उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के 31 दिसम्बर तक की जाएगी और पूर्ण की जाएगी जिसके लिए परियोजना सेल्फ और श्रमिक बजट तैयार किया जा रहा है ।

(न) श्रमिक बजट चक्र अप्रैल से मार्च तक होगा ।

(य) कार्यान्वयन अभिकरण सभी स्तरों पर निष्ठापूर्वक और कड़ाई से समय सीमा का पालन करेगा और यदि कोई स्तर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर योजना प्रस्ताव का अनुमोदन करने में असफल रहता है तो उसे अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और अनुमोदन का अगला स्तर प्रस्तावों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(फ) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत तक जिलों के श्रमिक बजट को अपनी सिफारिशों के साथ यह प्रमाणित करते हुए केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी कि अधिनियम और उसके अधीन

बताए गए नियमों में यथा परिकल्पित सभी कानूनी उपबंधों का श्रमिक बजट तैयार करने में अनुपालन किया गया है ।

(ब) केन्द्रीय सरकार श्रमिक बजट की लागत को पूरा करने के लिए अपेक्षित केन्द्रीय निधि का अवधारण करने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के लिए तंत्र का गठन करेगी ।

(भ) किसी विशिष्ट वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रमिक बजट के मूल्य निर्धारण और संबंधित ग्राम और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ब्लाक पंचायतों तथा जिला पंचायत के अनुमोदन से राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रद अधिकारिता प्रदान किए जाने के पश्चात् अतिरिक्त संकर्म अनुज्ञेय होगा ।

(म) जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम अधिकारियों और सभी ग्राम पंचायतों को तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरियों सहित अनुमोदित श्रमिक बजट तथा परियोजना सेल्फ के बारे में सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

7. केन्द्रीय निधि की मात्रा अवधारित करने वाले कारक,-

केन्द्रीय निधि की मात्रा निम्नलिखित कारकों के आधार पर अवधारित की जाएगी :-

(क) प्रति दिन प्रति व्यक्ति औसत लागत अधिसूचित मजदूरी दर से उच्चतर लागत पर संगणित नहीं की जाएगी और प्रशासनिक व्यय तथा तात्त्विक लागत का अनुपात विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा ।

(ख) मजदूरी तात्त्विक अनुपात 60: 40 होगा :

परंतु अकुशल मजदूरी लागत साठ प्रतिशत से अधिक हो सकेगी किन्तु तात्त्विक लागत चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ग) अकुशल कर्मकारों की मजदूरी मस्टर रोल में यथा अभिलिखित कर्मकारों की वास्तविक संख्या, किए गए कार्य और मजदूरी संदाय पर आधारित होगी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय मदों के संबंध में प्रशासनिक व्यय ।

(ङ) प्रशासनिक व्यय और सामग्रियों संबंधी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्टरों में अभिलिखित व्यौरों पर आधारित होगा ।

8. निधियां जारी करने की रीति,-

(१) राष्ट्रीय निधि से राज्य विधि को -

(क) जहां तक संभव हो केन्द्रीय निधियां दो भागों में ज्ञारी की जाएंगी ।

(ख) केन्द्रीय निधि के पहले भाग के अंतर्गत प्रारंभिक अतिशेष के समायोजन के पश्चात् मजदूरी पर आधारित श्रमिक बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष के पहले छह मास के लिए अपेक्षा समिलित होगी ।

(ग) केन्द्रीय निधि का पहला भाग वित्तीय वर्ष के आरंभ में जारी किया जाएगा ।

(घ) केन्द्रीय निधि का पहला भाग केवल उन राज्यों को जारी किया जाएगा जिन्होंने पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निधियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(ङ) राज्य सरकार, राज्य निधि में उपलब्ध निधियों के साठ प्रतिशत का आयोग करने के पश्चात्, उपयोगिता प्रमाणपत्र और अद्यतन जिलेवार प्रारंभिक अतिशेष, जारी निधियों (केन्द्रीय निधि और राज्य अंश पृथक रूप से), कुल उपलब्ध निधियों, संदर्भाधीन वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियों और उपलब्ध निधियों का ब्यौरा देने वाले विवरण के साथ दूसरे और पश्चातवर्ती भाग को जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगी ।

(च) राज्य सरकार निधियों के लिए सर्वप्रथम जिले द्वारा मांग किए जाने के बिना वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेगी ।

(छ) दूसरे और पश्चातवर्ती भागों की मात्रा का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा वास्तविक मांग और रिपोर्ट की गई व्यय की स्थिति के जिलेवार आंकड़े और मासिक प्रगति रिपोर्टों, प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा श्रमिक बजट प्रक्षेपणों से उसकी संगतता के आधार पर किया जाएगा ।

(ज) जारी किए जाने के प्रस्ताव को विनिर्दिष्ट प्ररूप में व्यय विवरण के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए व्यय से मजदूरी के संदाय, सामग्री की लागत और प्रशासनिक अधिक व्यय संबंधी व्यय अभिप्रेत है ।

(2) राज्य निधि से जिलों को -

(क) निधियों केन्द्रीय सरकार से निधियों की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर जिलों को जारी की जाएगी ।

(ख) राज्य से जिलों को निधि की मात्रा जिले के श्रमिक बजट पर आधारित कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

(ग) राज्य सरकार ऐसी निधियों के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक प्राप्त किए गए निधि के भाग को आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य निधि में आरक्षित के रूप में रखेगी ।

(घ) राज्य सरकार जिलों को सीधे निधियां जारी करेगी ।

(ङ) जिले एक बार उनके द्वारा अप्रेषित अतिशेष, केन्द्रीय निधि, राज्य निधि और प्रकीर्ण प्राप्तियों से मिलकर बनने वाली उपलब्ध निधि के साठ प्रतिशत का उपयोग करने पर अपने अगले भाग के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगी ।

(च) वे निधियां जो कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों, ब्लाकों, ग्राम पंचायतों को अग्रिम के रूप में दी गई हैं उपयोग की गई निधियों के रूप में दर्शित नहीं की जाएंगी ।

(छ) केवल मजदूरी, सारवान और अनुज्ञेय प्रशासनिक अधिव्ययों के वास्तविक संदाय के संबंध में उपयोग की गई निधियों की रिपोर्ट उपयोग की गई निधियों के रूप में की जाएगी ।

(ज) राज्य सरकार, निधियां जारी करने के पूर्व जिलों के प्रस्तावों की संवीक्षा और परीक्षा करेगी ।

(3) जिला स्तर पर निधियों का अंतरण -

(क) जहां तक संभव हो जिले कार्यक्रम अधिकारी को सूचना देने के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे निधियां जारी करेंगे ।

(ख) जिलों से कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी की गई निधियां, संकर्मों की जिला योजना में अनुमोदित संकर्म के अंश और उन संकर्मों के लिए तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदनों में अनुमोदित तत्स्थानी वित्तीय रकम पर आधारित होंगी ।

(ग) निधियां, जिलों द्वारा, राज्य निधि से निधियों की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को दी जाएंगी ।

(घ) ऐसी ग्राम पंचायतें और अन्य कार्यान्वयन अभिकरण, जो जिलों से सीधे निधियां प्राप्त करते हैं वे कार्यक्रम अधिकारी को सूचना देने के अधीन रहते हुए उपलब्ध निधियों का साठ प्रतिशत उपयोग करने के पश्चात् निधियों के अपने अगले भाग के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को आवेदन कर सकेंगे ।

(ङ) उन दशाओं में, जिनमें जिलों से निधियां कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से दी जाती हैं, ग्राम पंचायतें और अन्य कार्यान्वयन अभिकरण अगले भाग के लिए कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और कार्यक्रम अधिकारी उनके द्वारा उपलब्ध निधियों का साठ प्रतिशत उपयोग करने के पश्चात् अगली किस्त के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को आवेदन कर सकेगा ।

(च) उन निधियों को, जो कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अग्रिम के रूप में दी गई हैं, उपयोग की गई निधियों के रूप में दर्शित नहीं किया जाएगा ।

(छ) जिले निधियां जारी करने के पूर्व कार्यान्वयन अभिकरणों के प्रस्तावों की संवीक्षा और परीक्षा करेंगे ।

(4) राष्ट्रीय निधि से सीधे जिलों को -

ऐसे राज्यों की दशा में जिन्होंने राज्य निधि स्थापित नहीं की है, राष्ट्रीय निधि से केन्द्रीय निधियां सीधे जिलों को जारी की जाएंगी और ऐसे मामलों में नियम 8 और नियम 9 में विनिर्दिष्ट शर्तें यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी ।

9. पश्चात्तवर्ती भागों के संबंध में राष्ट्रीय निधि से राज्य निधि को केन्द्रीय निधियां जारी करने की शर्तें :

नियम 8 के उपनियम (1) के खंड (डे) में निर्दिष्ट पश्चात्तवर्ती भागों के संबंध में राज्य निधि को केन्द्रीय निधियां निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के अधीन रहते हुए जारी की जाएंगी--

(1) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 22 की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य निधि में ऐसी रकम जमा करेगी और निम्नलिखित अग्रेषित करेगी-

(i) राज्य का अंश मंजूर करने वाले आदेश की प्रति ;

(ii) राज्य अंश में जमा राशि उपदर्शित करने वाले बैंक विवरणी की प्रमाणित प्रति, जो शाखा प्रबंधक और जिला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना खाते कमे भारसाधक लेखा अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित हो ;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए राज्य निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र ; और

(iv) प्रारंभिक अतिशेष, जारी की गई निधियों (केन्द्रीय निधि और राज्य अंश पृथक् रूप से), प्रकीर्ण, प्राप्तियों कुल उपलब्ध निधियों, उपयोग की गई निधियों और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपलब्ध अतिशेष निधि का जिलेवार विवरण वाला राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित विवरण ।

(2) ग्रारंभिक अतिशेष, जारी की गई निधियों (केन्द्रीय निधि और राज्य निधियां, पृथक् रूप से), प्रकीर्ण प्राप्तियों, कुल उपलब्ध निधियों, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में क्रमशः जिलों द्वारा किया गया वास्तविक उपयोग और अंतिम अतिशेष के जिलेवार प्रमाणित विस्तृत विवरण के साथ राज्य निधि की बाबत समेकित संपरीक्षा रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे ।

(3) राज्य सरकार से यह प्रमाण पत्र कि प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं :-

(क) संपूर्ण संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें लेखाओं, तुलन पत्र, आय और व्यय विवरण तथा प्राप्ति और संदाय लेखे के साथ बैंक समाधान प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों के लेखे के संबंध में संपरीक्षक की टीका टिप्पणियां अंतर्विष्ट होंगी ;

(ख) प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रत्येक जिले की संपरीक्षा रिपोर्ट की टीका टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी ।

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र ।

(घ) संपरीक्षक का यह प्रमाण पत्र कि वर्ष के दौरान बुक किए गए प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत केवल वही आएंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर नियत मानकों के अनुसार अनुज्ञेय हैं।

(ङ) जिला कार्यक्रम समन्वयक का यह प्रमाण पत्र कि :-

- (i) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन यथा उपबंधित संकर्मों की लागत के अनुसार निधियों का कम से कम पचास प्रतिशत अनुबंधित अवधि के भीतर ग्राम पंचायतों को अंतरित कर दिया गया है;
- (ii) पूर्ववर्ती वर्ष का संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रारंभिक और अंतिम अतिशेष और उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शित प्रारंभिक और अंतिम अतिशेष पूर्ववर्ती वर्ष के समान है ;
- (iii) प्रबंध सूचना प्रणाली पूर्ण रूप से परिचालन में है ;
- (iv) कर्मकारों को मजदूरी का संदाय पृथक डाकघर/बैंक खाते के माध्यम से किया जा रहा है ;
- (v) मजदूरी के रूप में संदत रकम समसामयिक रूप से गृहस्थों के कार्य कार्ड में प्रविष्ट कर दी जाएगी ;
- (vi) प्राप्त की गई सभीक निधियां केवल बचत बैंक खाते में ही जमा की गई हैं ।

10. केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को अनुदान -

- (1) केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को, परिषद् को समानुदेशित कृत्यों के संबंध में व्ययों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय निधि से पांच करोड़ रुपए का प्रारंभिक समूह सहित अनुदान दिया जाएगा ।
- (2) परिषद् इस प्रकार दी गई निधियों के लिए किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक खाता रखेगी ।
- (3) परिषद् को अनुदान पूर्व वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट और पहले जारी की गई रकम का कम से कम साठ प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए जाने के पश्चात् ही दिया जा सकेगा ।

11. अतिशेष बजटीय अनुदान- प्रत्येक वर्ष का अतिशेष बजटीय अनुदान वित्तीय वर्ष के अंत से पूर्व राष्ट्रीय निधि में अंतरित किया जाएगा और वह राष्ट्रीय निधि में आरक्षिती का गठन करेगा ।

12. संपरीक्षा- राष्ट्रीय निधि से राज्य निधि को और सीधे जिलों को जारी किए गए अनुदान संबंधित महालेखाकारों के माध्यम से नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा के लिए खुले रहेंगे ।

आंतरिक संपरीक्षा, विभागाध्यक्ष, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की ओर से की जाएगी और मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा उसका पर्यवेक्षण और मानीटर किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11011/16/2007-एनआरईजीए]

अमीता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2009

G.S.R. 394(E).—The following draft rules namely the National Rural Employment Guarantee Financial Rules, 2009 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 20 read with sub-section(1) and clause (c) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) and in supersession of the National Employment Guarantee Fund Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby published as required by sub-section (1) of section 31, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi-110 001.

All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the National Rural Employment Guarantee Financial Rules, 2009;
 (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 (a) “Act” means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);
 (b) “Central Government” means the Central Government in the Ministry of Rural Development;
 (c) “Central fund” means the cost to be met by the Central Government as specified under sub-section (1) of section 22.

- (d) "National Fund" means the National Employment Guarantee Fund established under sub-section (1) of section 20;
- (e) "section" means a section of the Act;
- (f) "State Fund" means the State Employment Guarantee Fund established under sub-section (1) of section 21;
- (g) "State Government" shall include Union territory administrations.
- (h) "State share" means the cost to be met by the State Government as specified under sub-section (2) of section 22.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

3. National Fund.-

- (1) The National Fund shall be maintained by the Central Government in a Public Account.
- (2) The National Fund shall be utilised by the Central Government for meeting the Central Government share of expenditure as specified under sub-section (1) of section 22 of the Act, grants to the State Governments, the expenses of the Central Employment Guarantee Council, and such other expenditure incidental to the implementation of the Act.

4. State Fund.- (1) The State Government may establish a State Fund to be held in any Public Sector banks which shall be non-lapsable.

- (2) The State Government shall deposit in the State Fund its due share as specified under sub-section (2) of section 22 within a fortnight from the date of receipt of amount from the Central fund.

5. Grant of advances to the State Governments in certain cases.-

- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Government may, in order to meet emergent needs and temporary shortage of funds, give advances as it may consider necessary to the State or district, pending completion of formalities specified in these rules.
- (2) The Central Government may suspend release of Central funds to the State or district for improper use of funds, non-compliance of the provisions of the Act and/or the rules made thereunder: Provided that such releases shall be restored only after remedial measures have been effected by the concerned State or district.

Provided further that suspension of release of Central funds under this sub-rule shall not absolve the State Government of its liability to pay unemployment allowance under section 7 of the Act.

(3) The State Government or any other authority shall not create any encumbrance on the grants from the Central Government either received through the State Fund or received directly by the district or any other agency.

6. The quantum of Central fund.- The quantum of Central fund to be released to the State Governments shall be determined on the basis of the labour budget for the financial year prepared under sub-section (6) of section 14 of the Act, after assessment of the labour demand and shelf of projects in accordance with the following:-

(a) The Gram Panchayat shall estimate the labour demand likely to be raised in the next financial year and shall identify the projects that are expected to meet the estimated labour demand, as per recommendations of the Gram Sabha and the Ward Sabhas.

(b) Gram Panchayat shall prioritise and recommend the name of executing agencies for each work.

(c) Gram Panchayat shall submit a consolidated Gram Panchayat Development Plan for the next financial year to the Programme Officer along with a copy of its resolution and a copy of the minutes of the Gram Sabha and the Ward Sabhas' meeting by the end of September each year.

(d) The Programme Officer shall complete the scrutiny and coordination of Gram Panchayat Development Plans into a Block Plan and shelf of projects and ensure its submission for approval to Intermediate Panchayat within fifteen days of receipt of the proposals from the Gram Panchayats.

(e) The Intermediate Panchayat shall maintain the priority among different works as indicated by the Gram Panchayat and shall include only such works that involve more than one Gram Panchayat.

(f) The Intermediate Panchayat shall finalise and approve the Block Plan within fifteen days of its submission by the Programme Officer.

(g) In case Intermediate Panchayat does not approve the Block Plan within stipulated time, it shall be deemed approved by the Intermediate Panchayat.

(h) The Programme Officer shall submit the Block Plan to the District Programme Coordinator by the end of October each year.

(i) District Programme Coordinator shall scrutinise the Block Plans, examine the appropriateness and adequacy of works in terms of anticipated demand for unskilled manual work in the district as well as their technical and financial feasibility.

(j) District Programme Coordinator shall maintain the priorities of the Gram Panchayat and the Intermediate Gram Panchayat works as indicated in the Block Plan.

(k) In case of inadequacy of works, District Programme Coordinator may include those works whose jurisdiction is spread over more than one Block.

(l) The District Programme Coordinator shall consolidate Block Plans into a consolidated District Plan and shall ensure that at least fifty percent of works in terms of cost are to be executed by Gram Panchayats:

Provided that where there are works that are not to be executed by the Gram Panchayat, the District Plan shall indicate the executing agencies for the works included in the District Plan.

(m) District Plan shall contain the priority of works referred to in para 1 of Schedule I of the Act and in case of deviation from the priority of works stipulated in the Act, the District Development Programme Coordinator shall attach an explanatory note with the District Plan.

(n) District Programme Coordinator shall formulate the labour budget based on District Plan, in the format specified by the Central Government from time to time.

(o) If a sharp rise in the employment is estimated, proper justification for the same shall be clearly given in the labour budget.

(p) District Programme Coordinator shall submit the District Plan, Block-wise shelf of projects and the labour budget for the next financial year to the district Panchayat not later than November each year.

(q) The district Panchayat shall finalise and approve the District Plan, Block-wise shelf of projects and the labour budget, including technical sanction and administrative sanction of projects.

(r) The District Programme Coordinator shall forward the labour budget to the State Government certifying that labour budget has been approved by the District Panchayat, not later than 31st December each year.

(s) The entire exercise shall be undertaken and completed by 31st December of the year preceding the year for which the shelf of projects and the labour budget are being formulated.

(t) The labour budget cycle shall be from April to March.

(u) The implementing agency at all levels shall endeavour to scrupulously and strictly adhere to the time limit and if a level fails to approve the plan proposal within

the specified time-limit, it shall be deemed to have been approved and the next level of approval shall take necessary action on the proposals.

(v) The State Government shall forward the labour budget of the districts alongwith its recommendations to the Central Government by the end of January each year certifying that all statutory provisions as envisaged in the Act and rules made thereunder have been complied with in the formulation of the labour budget.

(w) The Central Government shall set up mechanism for consultation with the State Governments to determine the Central fund required to meet the cost of the labour budget.

(x) Additional works shall be permissible after appraisal of the labour budget by the Central Government for a particular year, and satisfactory justification provided by the District Programme Coordinator through State Government to the Central Government with the approval of the concerned Gram and Block Panchayats and the District Panchayat.

(y) The District Programme Coordinator shall be responsible for intimating to the Programme Officers and all Gram Panchayats the approved labour budgets and shelf of projects, along with technical and administrative sanctions.

7. Factors determining the quantum of Central fund.-

Quantum of Central funds shall be determined based on the following factors :-

(a) Average cost per personday shall not be calculated at a cost higher than the notified wage rate and the administrative expenses and the ratio of material cost shall not exceed the specified limit.

(b) Wage material ratio shall be 60 : 40 :

Provided that the unskilled wage cost may be more than sixty percent but the material cost shall not exceed forty percent.

(c) Wages of unskilled workers shall be based on the actual number of workers, work done and wage payment as recorded in the muster rolls.

(d) Administrative expenditure on permissible items as specified by the Central Government from time to time.

(e) Administrative expenditure and expenditure on materials shall be based on details recorded in the registers specified by the Central Government.

8. Manner of release of funds.-

(1) From the National Fund to State Fund.-

- (a) As far as possible, Central funds shall be released in two tranches.
- (b) The first tranche of Central funds would cover the requirement for the first six months of the financial year as per labour budget based on wage rate after adjustment of the opening balance.
- (c) The first tranche of Central funds shall be released at the beginning of the financial year.
- (d) First tranche of Central funds shall be released to only those States who have furnished utilisation certificate and audit report for the funds received during the financial year immediately preceding the previous one to the satisfaction of the Central Government.
- (e) The State Government may apply to the Central Government for the release of second and subsequent tranches after utilising sixty percent of funds available in the State Fund along with a utilisation certificate and a statement detailing upto date district-wise Opening Balance, Funds released (Central funds and State share separately), total available funds, funds utilised and balance funds available during the year under reference.
- (f) The State Government shall not submit financial proposal without the demand for funds being first raised by the district.
- (g) The quantum of second and subsequent tranches shall be decided by the Central Government based on district-wise data of actual demand and expenditure position reported by the State Government and its consistency with Monthly Progress Reports, Management Information System(MIS), and labour budget projections.
- (h) The proposal for release shall be submitted to the Central Government in the specified format with expenditure statement.

Explanation.- For the purpose of this clause, expenditure means expenditure on payment of wages, material cost and administrative overheads.

(2) From State Fund to districts.-

- (a) Funds shall be released to districts within fifteen days of receipt of funds from the Central Government.
- (b) The quantum of fund from State to the districts shall not exceed the total amount based on the labour budget of the district.

(c) The State Government may retain a portion of funds received not exceeding twenty five percent of such funds as a reserve in the State Fund to meet unforeseen exigencies.

(d) The State Government shall release funds directly to the districts.

(e) Districts may apply to the State Government for their next tranche once they have utilised sixty percent of available funds consisting of carry over balance, Central funds, State funds and miscellaneous receipts.

(f) Funds that have been given to Programme Implementing Agencies, Blocks, Gram Panchayats as advance shall not be shown as funds utilised.

(g) Funds utilised on actual payment of wages, material and permissible administrative overheads only shall be reported as funds utilised.

(h) The State government shall scrutinise and examine the proposals of the districts before release of funds.

(3) Transfer of funds at the district level.-

(a) Districts shall release funds as far as possible, directly to Gram Panchayats and other implementing agencies under intimation to the Programme Officer.

(b) Release of funds from districts to Programme officer, Gram Panchayats and other Implementing Agencies shall be based on the share of work approved in the District Plan of works and the corresponding financial amounts approved in the technical and administrative approvals for those works.

(c) Funds shall be released by districts to the Programme Officer, Gram Panchayats and other implementing agencies within fifteen days of receipt of funds from the State Fund.

(d) Gram Panchayats and other implementing agencies, who receive funds directly from the districts, may apply to the District Programme Coordinator for their next tranche of funds after they have utilised sixty percent of available funds under intimation to the Programme Officer.

(e) In cases where funds from districts are routed through the Programme Officer, the Gram Panchayats and other Implementing Agencies may apply to the Programme Officer for the next tranche and the Programme Officer may apply to the District Programme Coordinator for the next instalment after they have utilised sixty percent of available funds.

(f) Funds that have been given to Programme Officer, Gram Panchayats, and other Implementing Agencies as advance shall not be shown as funds utilised.

(g) The districts shall scrutinise and examine the proposals of the Implementing Agencies before release of funds.

(4) From National Fund directly to the districts:-

In the case of States, which have not set up the State Fund, the Central funds from National Fund shall be released directly to the districts, and the conditions specified in rule 8 and rule 9 shall apply mutatis mutandis in such cases.

9. Conditions for release of Central funds from National Fund to State Fund relating to subsequent tranches: The release of Central funds to the State Fund relating to subsequent tranches referred to in clause (e) of sub-rule (1) of rule 8 shall be subject to fulfillment of the following conditions:-

(1) The State Government shall deposit in the State Fund such amount for meeting the expenses as specified under sub-section (2) of Section 22 of the Act and shall forward -

(i) a copy of the order sanctioning the State share;

(ii) a certified copy of the Bank statement indicating the credit of the State share, duly authenticated by the Branch Manager and the Accounts Officer in charge of the National Rural Employment Guarantee Scheme account at the district level;

(iii) utilization certificate in respect of State Fund for the previous year; and

(iv) a statement certified by the State Government detailing district-wise Opening Balance, Funds released (Central funds and State share separately), miscellaneous receipts, total available funds, funds utilised and balance funds available for the previous year

(2) The consolidated audit report and utilisation certificate in respect of the State Fund alongwith a certified statement detailing district-wise opening balance, funds released (Central funds and State share separately), miscellaneous receipt, total funds available, actual utilisation by the respective districts and closing balance for previous financial year shall be forwarded by the State Government by 31st October each year to the Central Government.

(3) Certificate from the State Government that the following documents have been submitted by each District Programme Coordinator:-

(a) Complete Audit Report which shall contain the observations of the Auditor on the accounts, balance sheet, income and expenditure statement and receipt and payment

accounts along with Bank reconciliation certificate and accounts of implementing agencies for the previous financial year by 31st August each year:

(b) Action Taken Report on the observations of the Audit report of each district for the previous year shall also be submitted latest by 30th September each year.

(c) Utilisation certificate for the previous year.

(d) a certificate from the Auditor that the administrative expenditure booked during the year cover only those items which are admissible as per norms fixed by the Central Government from time to time.

(e) Certificate of the District Programme Coordinator that:-

(i) atleast fifty percent of funds in terms of cost of works as provided under sub-section (5) of Section 16 of the Act has been transferred to the Gram Panchayats within the stipulated period;

(ii) the opening and closing balance of Audit Report and the opening and closing balance shown in the Utilisation Certificate for the previous year are same;

(iii) the Management Information System(MiS) is fully operational;

(iv) wage payment to workers are being made through individual post office/bank accounts;

(v) amount paid as wages are being entered in the Job Card of the households simultaneously;

(vi) all funds received have been credited only to Saving Bank Account.

10. Grants to the Central Employment Guarantee Council.-

(1) The Central Employment Guarantee Council shall be given a grant with an initial corpus of five crores of rupees from National Fund in order to meet the expenses in connection with the functions assigned to the Council.

(2) The Council shall maintain a bank account in a Public Sector Bank for the funds so given.

(3) The grants may be given to the Council after audit report for the previous year and the utilisation certificate for atleast sixty percent of the amount already released are furnished.

11. Balance budgeted grants.- The balance budgeted grant of each financial year shall be transferred to the National Fund before the close of the financial year and shall constitute the reserve in the National Fund.

12. Audit.- The grants released from the National Fund to the State Fund and directly to districts shall be open to audit by the Comptroller and Auditor General through respective Accountant Generals. The internal audit shall be done on behalf of the Head of the Department, Department of Rural Development, Government of India and shall be supervised and monitored by the Chief Controller of Accounts.

[F. No. I-I1011/16/2007-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.